

**उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल**

**पहली अपील सं 134/2017**

श्रीमती. प्रेमा रौतेला .....अपीलकर्ता

बनाम

गोविंद सिंह रौतेला .....प्रतिवादी

उपस्थित: श्री सी ऐश रावत, अपीलकर्ता के अधिवक्ता।

श्री आर ऐश सम्मल, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता।

**कोरम: माननीय सुधांशु धूलिया, जे.**

**जे. माननीय रमेश चंद्र खुल्बे, जे.**

**माननीय न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, (मौखिक)**

यह तलाक की डिक्री के विरुद्ध पत्नी की अपील है, जो उसके पति (वर्तमान में इस अदालत के समक्ष प्रतिवादी) के पक्ष में दी गई है।

2. प्रतिवादी भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट में 'हवलदार' के रूप में कार्यरत है। अपीलकर्ता और प्रतिवादी का विवाह अल्मोड़ा में आई. डी. 1 पर संपन्न हुआ। वैवाहिक जीवन में, दंपति के दो बेटे हैं, जिनका नाम मंजुल और गौरव है, जिनकी वर्तमान आयु क्रमशः लगभग 14 और 12 वर्ष है। मान लीजिए, चूंकि पति/प्रतिवादी एक सेना कर्मी है और अक्सर क्षेत्र क्षेत्रों में तैनात रहता है, इसलिए पत्नी बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए अल्मोड़ा में किराए के आवास में रह रही थी, जो उनका गृह जिला है। उन्हें अल्मोड़ा शहर के एक स्कूल में भर्ती कराया जाता है, जिसे "कुरमांचल अकादमी" कहा जाता है। यह भी सबूत में आया है कि अपीलकर्ता के ससुर भी उनके साथ अल्मोड़ा में रहते हैं। आवास का किराया भी प्रतिवादी के पारिवारिक कोष से दिया जा रहा है। इन तथ्यों को शुरुआत में ही सही कहा गया है, क्योंकि पति (प्रतिवादी) द्वारा तलाक के लिए उठाए गए आधारों में से एक त्याग था।

3. 08.03.2014 को, सुबह के समय, अपीलकर्ता नैनीताल के पास "खुरपा ताल" के जंगलों में बेहोश पाया गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गई। जिस स्थान पर वह बेहोश पाई गई थी, वह लगभग 100 किलोमीटर दूर था। अल्मोड़ा में उनके निवास से। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा 08.03.2014 के शुरुआती घंटों में घायल अवस्था में पाए जाने पश्चात उसे पहले B.D पांडे Govt.Hospital नैनीताल में पर ले जाया गया और बाद में हल्द्वानी में सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के उच्च केंद्र में भेजा गया। सुशीला तिवारी सरकारी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट, जहाँ उन्हें नैनीताल से लाया गया था, से पता चलता है कि 31 वर्ष/एफ की आयु की प्रेमा रौतेला (अपीलार्थी) को सर्जरी वार्ड में भर्ती कराया गया था। रोगी को सिर पर हमले के कथित इतिहास के आधार पर 03 बजे पूर्वाह्न 8.3.2014 पर भर्ती कराया गया था, एक्स-रे से पता चलता है कि दाहिनी ओर फ्रैक्चर हो गया था और रोगी बेहोश था और चोटें "गंभीर प्रकृति की" थीं।

4. उसने ठीक होने के पश्चात 27.03.2014 पर विद्वान मजिस्ट्रेट के सामने दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 164 के से अपना बयान दिया। वह बताती है कि उसके सिर पर 42 टांके और मुँह के अंदर लगभग 10 टांके लगे हैं। फिर वह बताती है कि कैसे उसे 07.03.2014 की रात में पति और उसके चालक द्वारा "खुरपा ताल" नामक स्थान पर ले जाया गया था। उन्होंने पहले उसका गला घोटने की कोशिश की और उसके बाद उसके सिर पर वार किया गया और वह बेहोश हो गई और घाटी में गिर गई। अगले दिन उसे होश आया और "खुरपाताल" में स्थानीय लोगों की मदद से उसे पहले सड़क के किनारे, फिर बी डी पांडे सरकारी अस्पताल पर लाया गया। और अंत में सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में रेफर किया गया। इस घटना की पृष्ठभूमि में अपीलकर्ता का आरोप है कि उसके पति का किसी अन्य महिला के साथ संबंध था। विवेक के लिए, हम यहाँ इस महिला को मात्र "सुश्री ए" के रूप में संदर्भित करेंगे,

क्योंकि वह वर्तमान कार्यवाही में एक पक्ष नहीं है। अपीलकर्ता स्पष्ट रूप से कहता है कि इस महिला के साथ उसके पति के संबंध के कारण, उसने उसे मारने की योजना बनाई थी।

5. इस बीच, चूंकि अपीलकर्ता उसके घर में लापता पाया गया था और उसके दो नाबालिग बच्चे घर में थे, इसलिए उसके भाई द्वारा की गई पूछताछ पर वह उसके घर आया और बाद में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उसने अपने बहनोई के विरुद्ध अपने संदेह की ओर इशारा किया था। वर्तमान प्रतिवादी।एफ. आई. आर. प्राथमिकी होने के बाद, पुलिस ने जाँच की और प्रतिवादी और एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भा.दं.सं. सी. की खंड 364,307 के से आरोप पत्र दायर किया। इसके बाद पति और योगीश सांवाल को गिरफ्तार कर लिया गया और वे महीनों तक जेल में रहे।

6. इस बीच, पीछे के चैनलों को पति द्वारा दोस्तों और परिवार के सदस्यों के रूप में सक्रिय किया गया था।इसलिए एक समझौते का संदर्भ है जिसमें कहा गया है कि अब दोनों पक्ष सौहार्दपूर्ण तरीके से रहने के लिए सहमत हो गए हैं।एक महिला "सुश्री ए" का भी संदर्भ है, और पति का एक वचन है कि अब से उनका "सुश्री ए" के साथ कोई संपर्क नहीं होगा।

7. आपराधिक विचारण के बारे में जितना कम कहा जाए, उतना ही बेहतर है।वर्तमान अपीलकर्ता और सभी गवाह मुकर गए और प्रतिवादी और योगेश सांवाल को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा द्वारा 5.7.2014 पर बरी कर दिया गया!

8. इस न्यायालय के समक्ष पूरी की गई घटनाओं के पूरे क्रम में एक अत्यंत चिंताजनक और कुरूप पहलू यह रहा है कि प्रतिवादी और कुछ सीमा तक अपीलकर्ता ने भी न्यायालय के तंत्र का दुरुपयोग किया है

9. हम यह कहते हैं कि दोषमुक्ति के तुरंत पश्चात पति क्या करता है कि वह उत्तर प्रदेश के आगरा में परिवार न्यायालय के समक्ष अपनी शादी को भंग करने के लिए याचिका दायर करता है!यह एक स्वीकृत तथ्य है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

की खंड 19 के संदर्भ में आगरा की अदालतों का इस मामले पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। उस याचिका में, लिए गए आधार त्याग और क्रूरता के थे, और इस याचिका को बाद में 06.03.2017 पर वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया था। 06.03.2017 दिनांकित आदेश मात्र निम्नानुसार कहता है:

*"मामला प्रस्तुत किया गया था। मामला उठाया गया। अभियोक्ता उपस्थित है। उन्होंने अपनी याचिका को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया है क्योंकि वह इस याचिका को दबाना नहीं चाहते हैं और वह इसे वापस लेना चाहते हैं और अनुरोध करते हैं कि इस आशय के आदेश पारित किए जाएं।*

*अभिलेख को सुना और पढ़ा।*

*चूंकि अभियोक्ता अपनी याचिका को दबाना नहीं चाहता है, इसलिए उसकी याचिका न्यायाधीश के हित में स्वीकार की जाती है, और नियम के अनुसार अभियोक्ता को शिकायत वापस की जाती है।"*

10. उपरोक्त आदेश दिनांक 18.03.2017 से दो सप्ताह से भी कम समय में, अभियोक्ता, प्रतिवादी ने इसी तरह की राहत के लिए एक और मुकदमा दायर किया। विवाह के विघटन के लिए, त्याग और क्रूरता के समान आधार पर। इस बार याचिका परिवार न्यायालय, अल्मोड़ा, उत्तराखंड में दायर की गई थी। इसलिए निचली अदालत ने दो पहलुओं के संबंध में मुद्दे तैयार किए। जो कि त्याग और क्रूरता।
11. यहाँ यह देखना होगा कि क्या परिवार न्यायालय के पास इन दो आधारों पर कोई सबूत था। त्याग या क्रूरता पर!
12. हिंदू विवाह को निम्नलिखित आधारों पर पति या पत्नी द्वारा प्रस्तुत याचिका पर तलाक की डिक्री द्वारा भंग किया जा सकता है:

*(क) जिसके बाद विवाह संपन्न हुआ, एक पक्ष ने अपने पति या पत्नी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वैच्छिक यौन संबंध बनाए;*

*(ख) विवाह संपन्न हो जाने के पश्चात याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है;*

*(ग) याचिकाकर्ता को याचिका प्रस्तुत करने से ठीक पहले कम से कम दो साल की निरंतर अवधि के लिए छोड़ दिया है;*

*(घ) दूसरे धर्म में परिवर्तन करके हिंदू होना बंद कर दिया है;*

*(ङ) असाध्य रूप से अस्वस्थ दिमाग का रहा है, या लगातार या बीच-बीच में इस तरह के मानसिक विकार से पीड़ित रहा है और इस सीमा तक कि याचिकाकर्ता से प्रतिवादी के साथ रहने की उचित रूप से उम्मीद नहीं की जा सकती है।*

13. वर्तमान मामले में, तलाक के लिए एक याचिका आधार (बी) और आधार (सी) पर दायर की गई है, जो हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की खंड 13 की उप-खंड (1) के उप-खंड (आई) और (आई. ए.) के से दी गई है।

14. त्याग के लिए जो देखा जाना चाहिए वह यह है कि इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता ने याचिका की प्रस्तुति से तुरंत पहले कम से कम दो साल की निरंतर अवधि के लिए पति को त्याग दिया है। याचिका 18.03.2017 पर प्रस्तुत की गई थी। मान लीजिए, उससे पहले और अब भी अपीलकर्ता जो कि प्रतिवादी की पत्नी अपने ससुराल वालों के साथ अल्मोड़ा में किराए के मकान में रहती है। हालाँकि अपीलकर्ता का स्थायी निवास और वैवाहिक घर अल्मोड़ा के पास के गाँव में होगा, लेकिन वह अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के आदेश अल्मोड़ा में रह रही है, जो अल्मोड़ा में उपलब्ध है न कि उसके गाँव में। पति और पत्नी दोनों ने अल्मोड़ा में रहने का एक सचेत निर्णय लिया जिसके लिए पति और ससुराल वालों के धन से नियमित रूप से किराया दिया जा रहा है। अपीलकर्ता के ससुर भी अपीलकर्ता के साथ अल्मोड़ा में किराए के मकान में रहते हैं। हम यह भी देखेंगे कि वर्तमान वैवाहिक कार्यवाही में, अपीलकर्ता के ससुर ने वादी/प्रतिवादी (जो उसका बेटा है) के क्रूरता के साथ-साथ त्याग के हर दावे को खारिज करते हुए नीचे दी गई अदालत में एक शपथ पत्र दायर किया है। हम इस पहलू पर बाद में आएंगे। संक्षेप में, सभी प्रभावी उद्देश्यों के लिए, अपीलकर्ता अल्मोड़ा में अपने वैवाहिक घर में रह रही थी। इसे त्याग नहीं कहा जा सकता है। पलायन कहाँ है? इस संबंध में निचली विचारण न्यायालय के सआत्यन्तिक रूप निष्कर्ष पूरी तरह से विकृत हैं।

15. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 तलाक की डिक्री द्वारा विवाह को भंग करने के आधारों में खंड एक के रूप में "त्याग" को निर्धारित करती है। खंड 13 में दिए गए सटीक शब्द (i -ख) वे स्थान हैं जहाँ पति या पत्नी ने याचिका प्रस्तुत करने से ठीक पहले कम से कम दो साल की निरंतर अवधि के लिए याचिकाकर्ता को छोड़

दिया है। फिर भी, हाथ में मामले में, इस प्रभाव का कोई निष्कर्ष नहीं है। हमारे पास यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि प्रतिवादी ने आगरा में तलाक के लिए पहली याचिका कब दायर की, क्योंकि हमारे पास मात्र 06.03.2017 का आदेश है, जिसके द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था। इसलिए, यह मानते हुए भी कि जिस याचिका पर विचार किया जाना है, वह अल्मोड़ा में अदालत के समक्ष दायर याचिका है जब इसे 18.03.2017 पर दायर किया गया था, ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है कि अपीलकर्ता ने याचिका दायर करने से दो साल पहले प्रतिवादी को छोड़ दिया था। मान लीजिए, अपीलकर्ता अपने दो बच्चों और अपने ससुर के साथ अल्मोड़ा में रह रही है। उसके पति जो कि प्रतिवादी एक सेना का व्यक्ति होता है जो क्षेत्र क्षेत्रों और अन्य स्थानों पर तैनात होता है। अपीलकर्ता ने अपना वैवाहिक घर कहाँ छोड़ा है?

16. "परित्याग" को हालांकि अधिनियम के से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के एक समूह द्वारा अच्छी तरह से स्थापित है। यद्यपि यह अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की बात है, फिर भी इसमें दो तत्व होने चाहिए। अलगाव का एक तथ्य एनिमस डेसेरेन्डी या रेगिस्तान के इरादे के साथ होना चाहिए। रिपोर्ट किए गए **बिपिनचंद्र जयसिंहबाई शाह बनाम प्रभावती** के मामले में बहुमत द्वारा दिए गए मौलिक निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी व्याख्या की गई है। जिसका बाद में **लक्ष्मण उतमचंद्र कृपलानी बनाम मीना उपनाम मोटा** के मामले में पालन किया गया था, ने **ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 40** में रिपोर्ट किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

"जहाँ तक त्याग करने वाले पति या पत्नी का संबंध है, त्याग के अपराध के लिए दो आवश्यक शर्तें होनी चाहिए, (1) अलगाव का तथ्य, और (2) स्थायी रूप से सहवास को समाप्त करने का इरादा (एनिमस डेसेरेन्डी)। इसी तरह जहाँ तक परित्यक्त जीवनसाथी का संबंध है, दो तत्व आवश्यक हैं: (1) सहमति की अनुपस्थिति में, और (2) व्यवहार की अनुपस्थिति में जो पति या पत्नी को वैवाहिक घर छोड़ने का उचित कारण देती है ताकि आवश्यक इरादा बनाया जा सके..... प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। निष्कर्ष कुछ ऐसे तथ्यों से लिया जा सकता

हैं जो किसी अन्य मामले में एक ही निष्कर्ष की ओर ले जाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं; अर्थात्, तथ्यों को उस उद्देश्य के रूप में देखा जाना चाहिए जो उन कृत्यों द्वारा या इरादे के आचरण और अभिव्यक्ति द्वारा प्रकट होता है, दोनों अलगाव के वास्तविक कृत्यों के पूर्व और बाद में। यदि, वास्तव में, एक अलगाव रहा है, तो आवश्यक प्रश्न हमेशा यह है कि क्या उस कार्य को एक एनिमस डिसेरेन्डी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। परित्याग का अपराध तब शुरू होता है जब अलगाव का तथ्य और एनिमस डिसेरेन्डी सह-अस्तित्व में होते हैं। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वे एक ही समय पर शुरू हों। हो सकता है कि वास्तविक अलगाव आवश्यक दुश्मनी के बिना शुरू हुआ हो या यह हो सकता है कि अलगाव और दुश्मनी समय के साथ मेल खाते हों।"

17. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने कभी भी अपना वैवाहिक घर नहीं छोड़ा था। जिस घर में वह अपने बच्चों और ससुर के साथ अल्मोड़ा में रह रही है, वह सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उसका वैवाहिक घर है। भले ही प्रतिवादी और अपीलकर्ता के बीच कोई अलगाव या कृत्रिम अलगाव हो, लेकिन अपीलकर्ता की ओर से कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए पलायन की आवश्यक सामग्री कभी भी स्थापित नहीं की गई है।

18. क्रूरता के बारे में जितना कम कहा जाए, उतना ही बेहतर है। कथित तौर पर पति के अलावा किसी और द्वारा नहीं किए गए अपराध के लिए निचली विचारण न्यायालय द्वारा एक लाभ दिया गया है। हम पहले ही 7.3.2014 की घटना का उल्लेख कर चुके हैं और दिखा चुके हैं कि कैसे अपीलकर्ता को उसके पति द्वारा उसके घर से बाहर निकाला गया था, जिसने उसे मारने की योजना बनाई थी। न मात्र हमारे सामने चिकित्सा रिपोर्ट है, बल्कि ऊपर उल्लिखित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के से उनके बयान को यहां विस्तार खंड बताए जाने की आवश्यकता है। वह अपने बयान में (धारा 164 सी. आर. पी. सी. के तहत) कहती है कि उसकी शादी वर्ष 2002 में गोविंद सिंह रौतेला खंड हुई थी और शादी के समय खंड उनके दो बेटे हैं जिनकी उम्र लगभग 12 वर्ष और 9 वर्ष है। उनके पति कुमाऊं रेजिमेंट में भारतीय सेना में हैं, और एक महिला के साथ उनके विवाहेतर संबंध हैं। सुश्री "ए"। उसे उक्त महिला से लगातार टेलीफोन कॉल आते हैं, और यह संबंध पिछले 3-4 वर्षों से चल रहा है। लगभग एक सप्ताह, उसे उसके पति ने सूचित किया कि उसने एक नई सैंट्रो कार खरीदी है, और

उसे यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए क्योंकि वह उसे आश्चर्यचकित करना चाहता था। उसके पति ने फिर उसे मध्य प्रदेश से फोन किया और कहा कि वह अल्मोड़ा आ रहा है। अल्मोड़ा आने पश्चात उसने अपीलकर्ता को फोन किया और कहा कि रात में दरवाजा खुला रखा जाना चाहिए। 07.03.2014 पर, लगभग 10 बजे p.m. वह कार और चालक को बाहर छोड़कर घर आया, और फिर कहा कि उसके चालक को "कोशी" नामक स्थान पर छोड़ दिया जाना है और अपीलकर्ता को अपनी नई कार में उस स्थान पर उसके साथ जाना चाहिए, जिसका उसने पालन किया। लेकिन "कोशी" के बजाय पति उसे अलग-अलग जगहों पर ले गया और कुछ समय पश्चात उसे पति और ड्राइवर दोनों पर संदेह हो गया। जब वह अपने भाई से संपर्क करना चाहती थी, तो पति ने अपीलकर्ता से मोबाइल फोन छीन लिया। फिर वे उसे रात में एक दूरदराज की जगह पर ले गए। अपीलकर्ता तब बताता है कि कैसे अपीलकर्ता के पति और चालक ने उसका गला घोटने की कोशिश की। इसके बाद उसके सिर पर एक वस्तु लगी और वह बेहोश हो गई। अगले दिन जब उसने खुद को एक "जंगल" में पड़ा पाया तो उसे होश आ गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल में उनके सिर में 42 टांके और मुंह के अंदर 10 टांके लगाने पड़े। इसके बाद उन्हें हल्द्वानी के उच्च केंद्र में भेज दिया गया। वह तब स्पष्ट रूप से बताती है कि यह उसका पति और चालक था जिसने उसे मारने की कोशिश की थी।

19. जैसा कि हम पहले ही ऊपर उल्लेख कर चुके हैं, परिवार के बुजुर्गों ने मामले में हस्तक्षेप किया, जिसके परिणामस्वरूप एक समझौता हुआ, और परिणामस्वरूप विचारण में सभी गवाह मुकर गए, और प्रतिवादी को बरी कर दिया गया। इस समझौते के साथ-साथ निचली विचारण न्यायालय की कार्यवाही का लाभ उठाते हुए, जिसके परिणामस्वरूप वह बरी हो गया, पति/प्रतिवादी ने विवाह को भंग करने के लिए निचली विचारण न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की, इस आधार पर कि उसकी पत्नी द्वारा उसके विरुद्ध हत्या के प्रयास का आरोप झूठा साबित हुआ है



क्योंकि उसे दोषमुक्ति दिया गया है, और पति के विरुद्ध झूठा आपराधिक आरोप लगाना क्रूरता के बराबर है। यह निचली विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, और निष्कर्ष दिया गया है कि यह पत्नी के हाथों क्रूरता के बराबर है। निचली विचारण न्यायालय ने पति के विवाहेतर संबंध के सिद्धांत को कोई विश्वास नहीं दिया है, और निचली विचारण न्यायालय इस पर कितनी गलत रही है, हम कुछ समय में बताएँगे।

20. हमें यह भी डर है कि निचली विचारण न्यायालय भी विचारण न्यायालय में साक्ष्य की सराहना करने में विफल रही है, जैसा कि किया जाना चाहिए था।

21. निचली विचारण न्यायालय का आदेश वैवाहिक जीवन पर लंबे और थकाऊ उपदेशों से भरा हुआ है। विवादित निर्णय लियो टॉल्स्टॉय और डेव म्यूर के उद्धरणों से शुरू होता है। निर्णय के अंत में पति के प्रति पत्नी के कर्तव्यों, और इसके विपरीत, और विवाह की पवित्रता पर लंबे व्याख्यान हैं। विद्वान न्यायाधीश यह भी कहते हैं कि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि पति गलत है, कभी-कभी पत्नी को भी दोष देना पड़ता है। फिर दहेज की बुराइयों, उन महिलाओं पर टिप्पणियां होती हैं जो अपने पति के विरुद्ध झूठे आरोप लगाती हैं, आदि।

22. एक न्यायाधीश के लिए लेखक महान कार्यों का उल्लेख करना ठीक है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *(ओमा उपनाम ओमप्रकाश और एक अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य, (2013) 3 एस. सी. सी. 440)* के फैसले में संदर्भित किया है। महान लेखकों, न्यायविदों, शिक्षाविदों और कानून शिक्षकों के विचार एक न्यायाधीश के लिए विचार के लिए भोजन हो सकते हैं, लेकिन अंततः एक अदालत को तथ्यों और उसके सामने साक्ष्य की जांच करने के पश्चात और बाध्यकारी उदाहरणों *(ओमा उपनाम ओमप्रकाश सुप्रा)* के आवेदन के पश्चात अपने समक्ष पूर्व निर्णय का फैसला करना होता है। उपरोक्त निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय को दरकिनार करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

*"हम यह इंगित कर सकते हैं कि न्यायिक निर्णय में स्पष्ट तर्क और विश्लेषण बुनियादी आवश्यकताएं हैं। न्यायिक निर्णय को पक्षकारों द्वारा और सामान्य रूप से समाज द्वारा कानूनी नियमों के सही अनुप्रयोग, स्थापित न्यायिक पूर्व निर्णय आधार पर तथ्यों के उचित मूल्यांकन का परिणाम माना जा रहा है और एक न्यायाधीश ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो लोगों के विश्वास को कमजोर करेगा।"*

23. नीचे दिए गए न्यायालय के आदेश की अत्यधिक मत है, और हमारी यह भी मत है कि मामले की ठीक से जांच नहीं की गई है।

24. हाथ में मामले में, हम एक बाद की घटना का भी उल्लेख कर सकते हैं, जिसका मामले में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तलाक का मुकदमा 27.09.2017 पर तय किया गया था। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की खंड 15 एक ऐसी अवधि निर्धारित करती है जब तक कि एक तलाकशुदा व्यक्ति पुनर्विवाह नहीं कर सकता है, जो अपील के लिए निर्धारित अवधि है जो 90 दिन है।

25. दूसरे शब्दों में, प्रतिवादी 90 दिन पूरे होने तक शादी नहीं कर सकता था, और अपील दायर नहीं की गई थी। ये दोनों स्थितियाँ आवश्यक थीं। हालाँकि, प्रतिवादी ने 15.11.2017 पर शादी यद्यपि जो तलाक यद्यपि डिक्री से मुश्किल से 49 दिन बाद है! और उन्होंने "सुश्री ए" के अलावा किसी और से शादी नहीं की है, जिनके विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा लगातार आरोप लगाए गए थे। हम इस विवाह के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि यह हमारे सामने मामला नहीं है। हमने मात्र यह तथ्य बताया है क्योंकि यह हमारे सामने एक स्वीकृत स्थिति है।

26. इन स्थितियों में, हमारा विचार है कि निचली विचारण न्यायालय पत्नी के विरुद्ध क्रूरता और त्याग के निष्कर्ष से पहुंचने में एक बड़ी त्रुटि में पड़ गई है। नतीजतन, हम अपील की अनुमति देते हैं और न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, अल्मोड़ा द्वारा पारित 27.09.2017 के निर्णय और आदेश को अपास्त कर देते हैं।

**(रमेश चंद्र खुल्बे, जे.)**

**18.03.2019**

**(सुधांशु धूलिया, जे.)**

**18.03.2019**